Pradesh. Here, I have a point which I would like clarified by the hon. Minister of State for Commerce. The Andhra Pradesh Co-operative Union was promised by the Central Government that it would also be given certain orders of the Russian Government. But nothing has happened during the last two years. The Government of India owes money to the Russian Government...*(Interruptions)*.... Let me come to the point, Madam. The Government of India owes money to the Russian Government and now discretion can be used and that money can be set off and, therefore, exports can be made. The Russian Government is willing to purchase provided more credit facilities are given. I would like to have the clarification from the honourable Minister.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Narayanasamy can be made the Commerce Minister!

THE DEPUTY CHAIRMAN: I heard the Minister saying that he has already persuaded and the Government has given some credit. I heard him say that.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Madam, there seems to be some misunderstanding which I would like to remove. It is being said that, on the one hand, I am asking the farmers not to grow and, on the other, I am persuading the Russians. But the problem is that from last year's stock there has been a carry-over of 28 million kgs. Where am I to send that tobacco? It is mainly for this carry-over stock of tobacco that we are trying to persuade the Russians, "Please buy tobacco from us; kindly buy tobacco from us.". That is the reason and that is the only solution.

SHRI CHATURANAN MISHRA: It is export of cancer!

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Madam, during his last visit, the Prime Minister appealed to the tobacco growers there, "This thing is not going to continue. You kindly switch over to some other cash crop.". For the information of the honourable House, I wish to say that a very systematic study has been made and the Tobacco Research Institute has carried out a study in which they have given the figures of different commodities, alternative commodities, to which the tobacco growers can switch over. The problem here is that the net profit per hectare is, of course, the highest in tobacco, that is, Rs. 8,600/-. Now, they have made a study and they have said that in the case of groundnuts, it is Rs. 7,400/-, in the case of soyabean, it is Rs. 6,500/- and in the case of sunflower, it is Rs. 4,160/- and so on. These are the alternatives about which they have given the information. And, Madam, time and again, the Tobacco Board, myself, the Commerce Ministry and Mr. Sivaji—he is also one of the members—have appealed to the people to switch over to other crops and the media also is being used for this purpose. So, the only solution is that we have to switch over ultimately to the other crops.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think we can now switch over to the next Question. Question No. 422.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Madam, I have been waiting for a long time to be called.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that. But, after the Prime Minister's explanation, there is nothing left to smoke out. Question No. 422.

** 422 [The questioner (Shri Anand Prakash Gautam) was absent. For answer, vide col. infra]*

New Technology of Motors

*423. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 159 given in the Rajya Sabha on the 5th August, 1993 and state:

(a) what is the total capital investment for adopting the new technology of motors;

(b) what is the break-up of total collaboration, royalty, design and engineering charges, training and hiring of experts etc. in each of the relevant financial year;

(c) what is the break-up of materials component and finished machines imported from collaborators and their subsidiaries in each of the relevant financial year; and

(d) whether BHEL has paid royalty charges to Siemens (Germany) for machines designed as per its earlier collaborators; if so, the details including the total royalty charges paid on such machines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY

INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The total capital investment for adopting the new technology was Rs. 26 crores approximately.

(b) and (d) Details are given in Statement-I (*See below*). The total royalty of Rs. 655 lakhs includes, about Rs. 243 lakhs paid for using SIEMENS information and design features for improving motors based on earlier designs.

(c) Details are given in Statement-II.

Statement I

S. No.	Year	Rs./Lakhs Approx. Collaboration, Design Engineering and Training (Lump-sum)	Royalty	Hiring Charges for Siemens Experts
1.	1981-82	46	-	-
2.	1982-83	70	-	-
3.	1983-84	80	-	-
4.	1984-85	155	-	14
5.	1985-86	52	76	15
6.	1986-87	-	58	14
7.	1987-88	-	85	29
8.	1988-89	-	112	23
9.	1989-90	-	134	3
10.	1990-91	-	154	1
11.	1991-92	-	36	-
	Total	403	655	99

Statement II

S. No.	Year	Rs./Lakhs Approx. Finished Machines	Materials and Components
1.	1984-85	250	200
2.	1985-86	250	280
3.	1986-87	200	220
4.	1987-88	100	180
5.	1988-89	150	150
6.	1989-90	50	170
7.	1990-91	130	100
8.	1991-92	20	50
	Total	1150	1350

GRAND TOTAL Rs. 2500 Lakhs

THE DEPUTY CHAIRMAN : Will I be allowed to hear what the Minister says? Will the honourable Members keep quiet?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मेडम, बी०एच०ई०एल० के कोलेबरेशन के बारे में बहुत बार पहले भी सवाल उठे हैं। यह अच्छी बात है कि अब पुराने एग्रीमेन्ट्स खत्म हो गये हैं। लेकिन अनुभव यह रहा है कि 655 लाख रुपए की रायल्टी के बाद भी प्रोडक्शन घटा है, प्रोडक्टिविटी घटी है। क्या इसकी वजह यह है कि सीमेन्स, जर्मनी के जो यहाँ एजेन्ट हैं, सीमेन्स इंडिया, यह सारे डिजायन और टैक्नोलाजी के जो नक्शे आया करते थे वह उनके मारफत आते थे और सारे एग्रीमेन्ट्स केवल बन साहडेड हुए ? उसी का नतीजा है कि बी०एच०ई०एल० को यह सारा नुकसान भुगतना पड़ा। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि स्थिति को स्पष्ट किया जाय।

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, जो उत्तर दिया गया है वह अपने आप में पूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह अपूर्ण है तो मैं कहना चाहती हूँ कि 1981 में "भेल" ने सीमेंस के साथ इलेक्ट्रिक मोटर स्विच गियर के संबंध में टैक्नीकल जानकारी, नो-हाऊ, मैनुफैक्चरिंग टैक्नोलाजी प्राप्त करने के लिये दस वर्षों के लिये सहयोग समझौता किया था ताकि बड़े पेट्रो-रसायन, फर्टिलाइजर प्लांट और विद्युत-घरों के लिये इन सामग्रियों की आपूर्ति की जा सके। समझौते की अवधि अब समाप्त हो गयी है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि "भेल" से कोई फायदा नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूं कि मोटरों के लिये नयी टैक्नोलाजी का औचित्य था। यह इसलिये कि "भेल" के पास उस वक्त उपलब्ध डिजाइन पुराने हो गये थे। मोटरें कम क्षमता की थीं। उनके ग्राहकों को उन्नत एवं विश्वस्त डिज़ाइन चाहिये थे। यह तो आप सभी जानते हैं कि आज कंपीटीशन का युग है और जब कंपीटीशन सामने आता है तो उसको भी उसके साथ-साथ चलना पड़ता है।

क्राम्पटन ग्रीव्स, किर्लोस्कर और एन० जी० ई० एफ० जैसे "भेल" के कंपीटीटर्स थे। उन्होंने भी अपनी टैक्नोलाजी का आधुनिकीकरण किया था जिसके चलते "भेल" के प्रोडक्ट को खतरा था। अतः मोटरों के डिज़ाइन को बनाये रखने के लिये सीमेंस के सहयोग से "भेल" को अपनी टैक्नोलाजी का आधुनिकीकरण करना ही पड़ा। सीमेंस विश्व में बड़े निर्माताओं में से एक है। यह समझौता सरकार के अनुमोदन से किया गया।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : महोदया, क्या यह सच है कि

भी०एच०ई०एल० का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, उसमें भी वह किसी भी चीज को बिना कोलाबरेशन के पूरा करने की क्षमता नहीं रखता। आज भी अगर यह जानकारी सही है तो करीब-करीब 35 ऐसे एग्रीमेंट हैं जिन पर कोलाबरेशन किया जा रहा है और फिर से सीमेंस इस बात की कोशिश में है कि उनको फिर से कोलेबरेटर बना दिया जाय। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि अब सीमेंस जर्मनी के साथ कोलाबरेशन का कोई फायदा न किया जाकर इन मामलों में ग्लोबल टेंडर मंगाकर ही फैसले किये जायेंगे ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदय, जहां इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कही है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि टैक्नोलाजी में हमेशा परिवर्तन और उन्नति होती ही रहती है। अपने आप उपलब्ध टैक्नोलाजी को अद्यतन बनाये रखने के लिये "भेल" जागरूक है। देश की आवश्यकताओं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिये "भेल" नयी टैक्नोलाजी और नये अवसरों की खोज करता है। वर्तमान वर्ष में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और विकास कार्यों के लिये उसका 51 करोड़ रुपये का बजट है। "भेल" द्वारा अनुसंधान कार्यों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि भारतीय कंडीशंस के अनुकूल किस प्रकार की टैक्नोलाजी उपयुक्त होगी, किस तरह की टैक्नोलाजी को अडाप्ट करेंगे तथा ग्राहकों के फीड बैक के आधार पर किस तरह से उसमें सुधार लाना है। उपसभापति महोदया, युग परिवर्तनशील है और हम अपनी टैक्नोलाजी का अपग्रेडेशन चाहते हैं, माडर्नाइजेशन चाहते हैं। तो अभी की स्थिति में ऐसा कुछ कह देना कि आगे कुछ नहीं किया जायेगा तो इससे राष्ट्र का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। इतना हम अभी कह सकते हैं कि हमारा जो 59 विदेशी कंपनियों से समझौता हुआ था इनमें से 45 समझौतों की अवधि समाप्त हो गयी है और वर्तमान में 14 चालू समझौते ही हैं।

उपसभापति : वह यह पूछ रहे हैं कि यह सिर्फ एक ही कंपनी से न करके आप ग्लोबल टेंडर बुलायेंगे या नहीं । आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है ?

श्रीमती कृष्णा साही : आवश्यकता पड़ने पर तो कहा जा सकता है। जैसी आवश्यकता होगी, आवश्यकतानुसार होगी।

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह जो सीमेन्स के साथ एग्रीमेंट करके जो काम किया गया है उसमें "भेल" को घाटा हुआ या नफा हुआ ? यह टोटेलिटी में बताना होगा। दूसरे देश से एग्रीमेंट करना कोई बिल्कुल सरेंडर करना नहीं होता है। लेकिन टोटेलिटी में हमको नफा हुआ या नुकसान हुआ एक तो यह बता दिया जाए, दूसरा यह बता दिया जाए कि यह चर्चा चली है कि "भेल" और सीमेन्स का ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा इस देश में ताकि यह वर्ल्ड में कम्पीट कर सके। यह कहां तक सच है। मंत्री महोदया कहां तक कम्पीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है यह हम जानना

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, "भेल" यह जो कोलेबोरेशन हुआ है उससे हम लाभ में रहे हैं। मैं कम्पेरीजन करना चाहती हूं पुराने और नये का। पहले हम एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते थे। यह मोटर की बात हो रही है। इसमें अब हम 45 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात मैं कह रही हूं क्योंकि मोटर्स का प्रश्न है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने एक्सपोर्ट नहीं पूछा है।

श्रीमती कृष्णा साही : फायदा पूछ रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : प्राफिट हुआ या लास हुआ। कितने का प्राफिट हुआ है ?

श्रीमती कृष्णा साही : प्राफिट हुआ है। पहले टोटल वेल्यू मैनुफैक्चर का 67 करोड़ था अब 500 करोड़ का है और पहले जो इस्तेमाल . . .(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो प्रोडक्शन हुआ। हमारी बात सुनिये।

श्रीमती कृष्णा साही : फायदा है ना।

श्री चतुरानन मिश्र : वेल्यू एडड प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। लेकिन प्राफिट हुआ या लास हुआ यह तो दूसरी बात है।

श्रीमती कृष्णा साही : प्राफिट हुआ है।

श्री चतुरानन मिश्र : तो बता दीजिए कितना प्राफिट हुआ है, यही तो हम जानना चाहते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं तो कह रही हूं।

उपसभापति : बता रही है। आप जरा धीरज लेकर बैठेंगे तो बता देंगी। आप जरा धीरज तो रखिए।

श्रीमती कृष्णा साही : बेनीफिट हुआ है . . .(**व्यवधान**) सुनियेगा न तो . . .(**व्यवधान**)

मैं कहना चाहती हूं कि हमें फायदा हुआ है। मोटर और स्विच गीयर्स के लिए आधुनिक टैक्नोलाजी प्राप्त हुई है। विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है, और नहीं तो हमें बड़ी मोटरों का आयात करना पड़ता। इसके चलते "भेल" की बिक्री भी बढ़ी है तथा "भेल" और अधिक विश्वसनीय मोटर्स और स्विच गीयर्स की आपूर्ति करता है। आपूर्ति की अवधि पूर्व के 12—14 माह के बदले अब 6 से 8 माह में घटायी गयी है। जहां तक वित्तीय लाभ की बात है "भेल" ने मात्र 11.5 करोड़ रुपए का टैक्नोलाजी के लिए भुगतान किया था जबकि समझौते की अवधि में उसने लगभग 500 करोड़ की बिक्री की है।

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरा हिस्सा ज्वाइंट सेक्टर वाला भी तो कह दीजिए।

श्रीमती कृष्णा साही : फिर से छेड़राहवे।

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरा हिस्सा मैंने यह कहा था कि यह चर्चा चली थी सीमेन्स और "भेल" दोनों का ज्वाइंट सेक्टर बनेगा और तब वर्ल्ड में कम्पीट करेंगे। उसकी क्या बात है?

श्रीमती कृष्णा साही : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने जवाब में एक चार्ट दिया है। इस चार्ट से पता लगता है कि सन् 1986-87 के बाद आपने ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। रायल्टी के लिए दिया है और एक्सपर्ट्स के किराये पर दिया है। इसका मतलब है कि आपने अपने जो एक्सपर्ट्स थे उनको ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं समझी। केवल रायल्टी और भाड़े पर जो आते हैं उनके लिए दे रहे हैं। यह स्थिति साफ करें। यह स्थिति क्यों है। आप बजाये इसके कि अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करें आपने 1986-87 से बंद कर दी है ट्रेनिंग और केवल आप उनको रायल्टी दे रहे हैं और उनको हायरिंग चार्जेज दे रहे हैं। यह तो बड़ी गलत बात होती है। क्या आप इस स्थिति को बदलना चाहेंगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, यह तो हमने अच्छी बात की कि वहां से जो प्रशिक्षण देने के लिए आये थे—आपको साफ मैंने कहा है कि यह अब खत्म हो गया है। हमारा जो एग्रीमेंट था और 1981 से लेकर 1986 तक आप देखिएगा कि कोलेबोरेशन, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग के लिए लम्प-सम हमने 5 इंस्टालमेंट्स में पैसे दिये हैं जो 403 लाख . . .**(व्यवधान)** में बता रही हूं . . .**(व्यवधान)** थोड़ा सा तो पेशंस रखिए . . .**(व्यवधान)** उपसभापति महोदया, . . .**(व्यवधान)**

उपसभापति : बोलिये। . . .**(व्यवधान)**

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : These bachelors do not know how to behave with women. That is the problem . . *(Interruptions)*

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापतिजी, यह तो हमें रोज भोगना पड़ता है। आप लोग जो करते हैं ना, वह प्रतिदिन भोगना पड़ता है। यहां उपसभापति हैं, यहां बैठी हैं—सब उसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूं। . . .**(व्यवधान)** यहां भी हैं, सब जगह हैं। मैं यह नहीं कहती कि जो माननीय हमारे सांसद हैं, उनसे कोई हम लोग इनफीरियर जवाब देते हैं, कि ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कुछ जवाब ही नहीं ठीक देते हैं।

हम लोग अच्छी तरह देते हैं और ज्यादा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को दूसरा कुछ डाइवर्शन नहीं है, काम ही करते हैं। आप लोग दूसरे-दूसरे काम बहुत करते हैं। . . .**(व्यवधान)**

उपसभापतिजी, पेमेंट्स हमने जो उनके साथ कोलेबोरेशन किया था विभिन्न मदों में, उसका भी भुगतान कर दिया है और जैसा कि मैंने कहा कि बिक्री के बाद की फीस हमने उनको दे दी और जब उसके बाद हमें आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने उनको कच्चे माल का पेमेंट किया, जो 25 करोड़ रुपये का है। अब उसके बाद आवश्यकता ही नहीं थी उसकी।

उपसभापति : गया सिंह जी, क्या आपको भी उत्तर मिल गया ? अगर मिल गया है तो—We can move on. . . *(Interruptions)*

SHRI SUKOMAL SEN : Her reply reflects the condition of industry in our country.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Indigenous industry.

श्री गया सिंह : मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि पाँच सौ करोड़ रुपये का लाभ अभी मंत्री महोदय ने बताया है, लेकिन आजादी के दिनों में भेल को इतना हाइली टैक्नोलोजी होने के बाद भी हमारे देश के जो विभिन्न पब्लिक सैक्टर हैं, वे भेल की आर्डर नहीं देकर विदेश में इन मोटरों के लिए आर्डर क्यों दे रहे हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापतिजी, प्रश्न तो इलैक्ट्रिक/पावर मोटर से संबंधित है और यह भेल के बारे में पूछ रहे हैं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता है जब भेल के ऊपर स्टाई या लन्स्टार्ड क्वेश्चन सदन में नहीं आया है। प्रश्न बिजली के मोटर से और पावर से संबंधित है, सम्पूर्ण भेल से सम्बन्धित नहीं है।

उपसभापति : नहीं वे सवाल यह पूछ रहे थे कि अगर भेल की काफी तरक्की हुई है और नई टैक्नोलोजी का आधुनिकीकरण हुआ है उसका, तो फिर भी दूसरे जो गवर्नमेंट कि डिपार्टमेंट हैं, वे भेल से क्यों नहीं खरीदते, बाहर से क्यों खरीद रहे हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापतिजी, आजकल जो कम्पीटीशन का युग है, ओपन कम्पीटीशन है, उदारीकरण की हमारी नीति है, लेकिन जहां तक भेल की परफार्मेन्स का सवाल है, वह बुरा नहीं है।

अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं बता सकती हूं।

Increase in Mango Export

*424. SHRI SHIV PRATAP MISHRA :
SHRI V. HANUMANTHA RAO :†
Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are making any special efforts to increase mango exports;

(b) whether any efforts have been made to facilitate mango exports from Andhra Pradesh; and

(c) what is the annual foreign exchange earned from mango export during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES,

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Hanumantha Rao.